नैनीताल मे कागज का कारखाना

4975. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कुछ बड़ी कम्पनियों ने नैनीताल के निकट पर्वतीय क्षेत्रों में कागज के कारखाने स्थापित करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किये थे;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में ऐसे कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के उचित उपयोग हेतु सरकारी कम्पनी बनाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सेन्चुरी पल्प की प्रतिवर्ष (1) 20,000 मी० टन अखबारी कागज, (2) 20,000 मी० टन छपाई का सफेद कागज और (3) 20,000 मी० टन रेयन ग्रेड लुग्दी का उत्पादन करने के लिए नैनी (उ० प्र०) में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

मै० नैनीताल पेपर लि० को प्रतिवर्ष 15,000 मी० टन लिखाई और छपाई कागज का निर्माण करने के लिए नैनीताल (उ० प्र०) में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाईसेंस जारी किया गया है।

(ग) फिलहाल इस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है।

Ineffectivity of T.V. sets in Pune (Maharashtra) in Summer season

4976. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received a written representation from Pune (Maharashtra) in the month of May 1977 regarding ineffectivity of TV sets in summer season;

(b) if so, action taken or proposed to be taken; and

(c) whether the persons concerned were accordingly intimated?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The interference is caused by a foreign station operating on the same frequency as Bombay, whose programmes are relayed by Pune. Alternate relay arrangements through P & T Departments microwave link are being engineered. These are expected to be completed by the end of 1977.

(c) Yes, Sir.

आयातित सामग्री से उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण

4977. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **उद्योग** मन्त्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो आयातित सामग्री से विदेशी सहयोग से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और उनके द्वारा कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी सभी सामग्री का आयात बन्द करने का है जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में काम आती

है ताकि भारतीय अर्थ व्यवस्था तथा देशी उद्योग सुदृढ़ हों; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

(ख) और (ग). 1977–78 के लिए बनाई गई आयात नीति को प्रधान उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, मूल्य विशेषकर सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखना है । प्रत्येक वस्तु के लिए नीति बनाते समय उद्योग की आयातित कच्चे माल की अपनी आवश्यकता तथा देश के निर्माणकर्ताओं के हितों के बीच न्यायिक संकलन को रखा गया है । मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि उस माल का आयात करने की अनुमति न दी जाय तो पर्याप्त मात्रा में देशी स्त्रोतों से मिल सकता है । फिर भी वर्षभर प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित नीति पर निरंतर ध्यान रखा जाता है ताकि जब कभी भी देश के उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक हो सुधार की कार्रवाई की जा सके । यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती है ।

Shifting of Transport companies from Shradhanand Bazar, Delhi

4978. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that despite repeated demand from the Public, transport companies have not so far been shifted from Shradhanand Bazar, in Delhi although sites had been reserved for them long ago;

(b) whether Government are also aware that these companies have virtually converted roads into their godowns and the flow of traffic is often blocked by parking trucks on road; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, about 55 transport companies who still have their offices in the Shradhanand Bazar area.

(b) There is no permanent encroachment on the roads by these transport companies in that area. However, the road in the area remains blocked by trucks for loading and unloading of goods. Goods are also sometimes kept on the road, though for short periods, before they are shifted to the transport companies' godowns.

(c) The encroachments on the road, as a result of keeping goods on it, are removed whenever raids are organised under the relevant provisions of Delhi Municipal Corporation Act.

Sites have been reserved at suitable places for the location of Transport Companies under the Master Plan of Delhi. Delhi Development Authority has planned/developed five transport centres, where some of the transport companies have already been shifted. Three sites are also proposed to be developed by Municipal Corporation of Delhi for the purpose.

Non-recognition of Tea garden Adivasis as Scheduled Tribes in Assam

4979. SHRI CHARAN NARZARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether tea garden and ex-tea garden Adivasis are not recognised as